



भारत में डजिटल भुगतान प्रणाली

॥



भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली

डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का अर्थ है डिजिटल डिवाइस या चैनल (बैंक ट्रांसफर, मोबाइल मनी, क्यूआर कोड आदि) का उपयोग करके एक भुगतान खाते से दूसरे भुगतान खाते में धन स्थानांतरित करना।



NPCI द्वारा भुगतान प्रणाली

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) खुदरा भुगतान हेतु एक व्यापक इकाई है (भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007)।

तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)

- खुदरा ग्राहकों के लिये
- सीमा-** ₹1-5 लाख (शुल्क+जीएसटी)
- 24/7 (तत्काल निपटान)
- प्रदाता:** बैंक, पीपीआई, मोबाइल वॉलेट कंपनियाँ

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)

- IMPS आधारित डिजिटल भुगतान ऐप के लिये प्रौद्योगिकी
- पुश एवं पुल हस्तांतरण
- फ्रॉस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया
- UPI-Lite+NFC:** ऑफलाइन भुगतान के लिये
- BHIM-UPI:** धन हस्तांतरण ऐप

रुपे कार्ड पेमेंट गेटवे (RuPay)

- 3 चैनलों में काम करता है:** - एटीएम, प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस, ऑनलाइन पोर्टल
- PMJDY के साथ निशुल्क दिया जाता है
- विदेशों में भी अपनाया गया (जैसे मॉरीशस)

विभिन्न पहलें

- भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) और यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम (UPMS)
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC)
- PAI चैटबॉट (एआई आधारित क्वेरी रिज़ॉल्यूशन)
- भारत QR
- ई-रूपी (e-RUPI)
- आधार पेमेंट ब्रिज (APB) प्रणाली
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)

RBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS)

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS)

- उच्च मूल्य के हस्तांतरण हेतु
- निम्न सीमा:** ₹2 लाख (कोई ऊपरी सीमा नहीं) (कोई शुल्क नहीं)
- 24/7 (तत्काल निपटान)
- बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उपलब्ध

लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (LPSS)

- NEFT/RTGS के लिये RBI का आपातकालीन विकल्प
- अस्थायी, पोर्टेबल समाधान



नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT)

- मध्यम-श्रेणी के हस्तांतरण हेतु
- RBI द्वारा कोई सीमा नहीं (कोई शुल्क नहीं)
- 24/7 (30 मिनट के अंतराल पर बैंकों के बीच सकल राशि का निपटान)
- बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उपलब्ध

डिजिटल भुगतान नियामक निकाय/सूचकांक

- डिजिटल हस्तांतरण लोकपाल
- भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS)



